100 पौधे लगाओ एनवायरोनमेंट हीरो का खिताब पाओ

30/6/2017

नगर निगम ने शहरवासियों के सामने चुनौती के साथ ही ऑफर पेश किया है। निगम सीमा के अंतर्गत 100 पेड़ लगाने वालों को एनवायरोनमेंट हीरो का खिताब दिया जाएगा। 100 पौधे लगाने के साथ ही इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेनी होगी । 'हरित बिलासपुर हर्षित बिलासपुर' योजना के तहत शहर के अमूमन हर क्षेत्रों में निगम ने हरियाली बिछाने की योजना बनाई है।

नगर निगम रेलवे क्षेत्र को छोड़कर शहर के अन्य वार्डों में हरियाली बिछाने फोकस करना शुरू कर दिया है। शहरवासियों के साथ ही युवाओं व अन्य सामाजिक संगठनों को इस मुहिम से जोड़ने के लिए निगम ने अनूठी योजना पर अमल करना शुरू कर दिया है । हरित बिलासपुर हर्षित बिलासपुर के तहत शहरवासियों के सामने 100 पेड़ लगाने की चुनौती रख दी है। पौधे लगाने के साथ ही इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने वालों को एनवायरोनमेंट हीरो के खिताब से नवाजने का एलान निगम ने कर दिया है। निगम के अफसरों का मानना है कि मौजूदा वर्ष जिस तरह तापमान में तेजी के साथ बढ़ोतरी हुई है उसे देखते हुए योजना से युवा वर्ग के अधिक से अधिक जुड़ने की संभावना है। चुनौतियों को स्वीकार करने और सकारात्मक सोच के कारण अफसरों को उम्मींद है यह योजना हिट हो जाएगी । शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 8 जुलाई से पौधारोपण की शुरुआत होगी। इसके पहले निगम प्रशासन ने शहरवासियों के बीच माहौल बनाने का निर्णय लिया है। सोशल मीडिया के अलावा अन्य माध्यमों से प्रचार प्रसार करने की योजना बनाई है। इसमें वॉल पेंटिंग के अलावा स्वंयसेवी संस्थाओं के बीच जाकर योजना का खुलासा करने और संस्था से जुड़े अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करने आह्वान किया जाएगा । इस अभियान से स्कूली बच्चों को भी जोड़ने की योजना बनाई गई है। स्कूलों के माध्यम से पौधारोपण के कार्य को अंजाम दिया जाएगा।

0 शहर में घूमेगा प्रचार रथ

अभियान से प्रत्येक वर्ग को जोड़ने के लिए प्रचार रथ भी घूमेगा। इसके जरिए मोहल्लों में पौधारोपण के लिए लोगों से अपील की जाएगी। पौधों का महत्व बताया जाएगा। पौधारोपण के लिए शहवासियों को शपथ दिलाने की योजना भी बनाई गई है। शपथ लेने वालों को पौधा लगाने व उसकी सुरक्षा की जिम्मेंदारी लेने कहा जाएगा। अभियान को प्रभावी बनाने स्वयंसेवी संस्थाओं से सुझाव लिया जाएगा।

हरित बिलासपुर हर्षित बिलासपुर योजना के तहत 100 पौधा लगाने व सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने वालों को एनवायरोनमेंट हीरो का खिताब देने की योजना बनाई है। अपनी तरह की पहली और अनूठी योजना है। उम्मीद है बड़ी संख्या में इस चुनौती को शहरवासी स्वीकार करेंगे । निगम को इसके लिए फ्रीहैंड दिया गया है।

अमर अग्रवाल

नगरीय प्रशासन मंत्री,छग शासन

पर्यावरण व ऑक्सीजन के लिए पौधारोपण की बनाएं योजनाः अमर

28/6/2017

नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल ने बुधवार को मंथन सभाकक्ष में आला अफसरों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण व ऑक्सीजन के दृष्टिकोण से बड़े पैमान पर पोधारोपण की योजना बनाने पर बल दिया। उन्होंने दोटूक कहा कि पौधा लगाना ही जरूरी नहीं है बल्कि उसका परिणाम महत्वपूर्ण है। प्लांटेशन के बाद पौधे जीवित रहें इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि हर वर्ष पौधारोपण के लिए अभियान चलाया जाता है। लेकिन इसकी सुरक्षा के उपाय नहीं होने से पौधे जीवित नहीं रह पाते। किस क्षेत्र में कौन-कौन से पौधे लगाए जिससे उस क्षेत्र को लाभ पहुंचे । इसकी योजना बनाकर पौधारोपण कार्य किया जाए । एक ही जगह पर बार-बार पौधे न लगार्या जाए। श्री अग्रवाल ने विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं को पौधारोपण के लिए उनकी मांग अनुरूप पौधे उपलब्ध कराने का निर्देश सामाजिक वानिकी विभाग के अधिकारी को

दिया। पौधों की सुरक्षा के लिए एनटीपीसी को ट्री गार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया । श्री अग्रवाल ने एनटीपीसी को जिले में हरियाली विकास के लिए विशेष योगदान करने कहा। स्कूलों में फेसिंग कर प्लांटेशन करने का निर्देश दिया। आंगनबाड़ी केंद्रों में आवश्यकतानुसार पौधे लगाने और स्वसहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पौधारोपण करने कहा। शहरी क्षेत्र के हर वार्ड में समिति बनाकर पौधारोपण के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित किया जाए । मोबाइल वेन के माध्यम से लोगों को पौधे वितरित करने कहा। उन्होंने बिलासपुर को हरा-भरा बनाने के लिए विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों से सुझाव भी देने कहा। कलेक्टर पी दयानंद ने बताया कि हरित बिलासपुर की संकल्पना के तहत् पूरी योजना के साथ शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पौधारोपण किया जाएगा और पौधारोपण के साथ-साथ उसकी सुरक्षा की योजना बनाई गई है। जिले में मनरेगा और विभागीय लक्ष्य अनुरूप पौधारोपण की तैयारी की गई है।

0 चावल उत्सव के दौरान कार्डधारकों को दिए जाएंगे पौधे

चावल उत्सव के दौरान राशन दुकानों से पौधे वितरित करने का निर्देश मंत्री श्री अग्रवाल ने दिया है। जिला पंचायत सीईओ श्रीमती फरिहा आलम सिद्दीकी ने बताया कि जिले में 54 लाख प्लांटेशन किया जाएगा । वन विभाग, सामाजिक वानिकी, उद्यानिकी विभाग के माध्यम से पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। बैठक में बिलासपुर एवं मरवाही वनमंडल, सामाजिक वानिकी, उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों ने विभागीय पौधारोपण के लिए अपने-अपने विभागों के लक्ष्य और उपलब्ध पौधों की जानकारी दी।

सभापति ने इंजीनियरों से पूछा बारिश में सीवरेज का क्या काम करोगे

26/6/2017

सभापति अशोक विधानी ने मंगलवार को अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम का काम देख रहे निगम के इंजीनियरों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने बारिश को देखते हुए सड़कों की खुदाई तत्काल बंद करने का निर्देश दिया।

सभापति ने निगम के ईई मनोरंजन सरकार व इंजीनियर सुरेश बरुआ सहित अन्य स्टॉफ की मीटिंग ली । बारिश के मौसम में जहां भी भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के लिए सड़कों की खुदाई की जा रही है उसे तत्काल बंद करने कहा। पाइप लाइन बिछाने के बाद गड्ढों की फिलिंग करने का निर्देश दिया । बारिश के मौसम में अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम के कौन-कौन से काम किए जा सकते हैं इसे लेकर उन्होंने इंजीनियरों से पूछताछ की । किस जोन के कितने प्रापर्टी चेंबर का काम शेष है। मेनहोल के कार्य की प्रगति के संबंध में भी जवाब-तलब किया । इसके अलावा प्रापर्टी चेंबर से घरों के कनेक्शन जोड़ने के काम को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने बारिश के दौरान इन्हीं कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की बात कही।

महापौर ने राजस्व अफसरों की ली बैठक

महापौर किशोर राय ने राजस्व अधिकारियों व मैदानी अमले की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने राजस्व वसूली को लेकर जोनवार जानकारी मांगी । टैक्स वसूली का कार्य ठेके पर देने से पहले निगम का अमला प्रतिदिन पांच से छः लाख रुपए की वसूली कर लेते थे। जब से कर वसूली का कार्य ठेके पर दिया गया है । राजस्व वसूली का आकंड़ा कम हो गया है। प्रतिदिन पांच हजार के करीब ही ठेकेदार के कर्मचारी वसूली कर पा रहे हैं। इसे लेकर महापौर ने नाराजगी जाहिर की । मेयर ने राजस्व विभाग के अफसरों व महकमे को वसूली कार्य में लग जाने का निर्देश दिया । उन्होंने कर वसूली की प्रत्येक सप्ताह समीक्षा करने की बात भी कही।

शहर का जलस्तर रिकार्ड 50 फीट गिरा

22/6/2017

पिछले साल हुई कम बारिश के कारण इस बार शहर का जलस्तर तेजी से गिरा है। आलम यह है कि गर्मी के अंत में 50 फीट तक पानी गिर गया है। इसके चलते पेयजल सप्लाई वाले बोर लगातार सूख रहे हैं। निगम 27 बोर में अतिरिक्त पाइप लगा चुका है। अगर अब भी जलस्तर नीचे जाना नहीं रुका तो हर वार्ड में पेयजल सप्लाई के लिए कम से कम एक-एक नए बोर कराए जाएंगे। इस तरह निगम को 58 नए बोर खोदने की जरूरत पड़ सकती है।

शहर की पूरी पेयजल सप्लाई व्यवस्था भू-जल पर निर्भर है। पिछली बार कम बारिश होने और शहर की जनसंख्या में बढ़ोतरी का सीधा असर पेयजल व्यवस्था पर पड़ रहा है। यही कारण है कि गर्मी की शुरुआत से ही जलस्तर में तेजी से गिरावट होनी शुरू हो गई थी। वर्तमान में गिरावट सबसे ऊंचे स्तर पर है। शहर में औसतन 50 फीट तक जलस्तर नीचे जा चुका है। निगम ने इसे देखते हुए अपने 27 बोर में पाइप नीचे उतारना पड़ा है। इसके बाद भी पानी जरूरत से बहुत कम मिल रहा है। कई जगहों में तो मुश्किल से एक घंटा बाद ही पंप से पानी आना बंद हो जाता है। इससे समस्या बढ़ गई है। निगम अधिकारियों का मानना है कि अगर इसी तरह जलस्तर नीचे जाता रहा तो सप्ताह भर बार संकट गहरा जाएगा। निगम को हर मोहल्ले में कम से कम एक-एक बोर करने पड़ेंगे। इस तरह 57 नए बोर का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। इसी तरह पानी टंकी से भी पेयजल सप्लाई मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में निगम को अब तेज बारिश का इंतजार है। अगर समय में पानी आ गया तो जलस्तर गिरने का संकट दूर हो जाएगा।

शहर में पेयजल संकट की स्थिति है। जलस्तर तेजी से गिर रहा है। अब तक 50 फीट तक पानी नीचे चला गया है। सामान्य दिनों में जहां 100 फीट में पानी आता था वह अब 150 फीट तक नीचे चला गया है। अगर एक सप्ताह यही स्थिति रही तो समस्या और बढ़ जाएगी।

अजय श्रीवासन

जल शाखा प्रभारी, नगर निगम

स्मार्ट सिटीः मिट्टीतेल लाइन सड़क पर होगा पहला काम

21/6/2017

शहर का नाम स्मार्ट सिटी में आने के साथ ही अब जल्द ही केंद्र से फंड भी मिलने की संभावना जताई जा रही है। यही कारण है कि निगम एक सप्ताह के अंदर विकास कार्यों की योजना बनाने कंसलटेंट नियुक्ति के लिए टेंडर जारी करने का निर्णय लिया है। स्मार्ट सिटी के तहत पहला काम मिट्टीतेल लाइन में चौड़ी सड़क तैयार करने का होगा। इसके बाद अन्य योजनाओं पर चरणबद्घ काम होगा।

केंद्र सरकार ने शहर का नाम स्मार्ट सिटी योजना में जोड़ दिया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अब क्या होगा। इसकी तैयारी पहले ही कर ली गई है। असल में योजना तैयार करने के साथ ही स्मार्ट सिटी बनाने के लिए एक अलग कंपनी बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड का गठन भी किया जा चुका है। इसके चेयरमैन नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव होंगे। जबकि सीईओ की जिम्मेदारी निगम आयुक्त को दी गई है। इस तरह अब इस कंपनी की बैठक करके पहले दो कंसलटेंट नियुक्त करने की कार्रवाई होगी। इसमें एक कंसलटेंट भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से विकास कार्य कहां और कैसे बनाना है,उसे प्रस्तावित करेगा। जबकि दूसरा कंसलटेंट आईटी सेक्टर के लिए योजना तैयार करेगा। इसी के साथ यह भी तय हो चुका है कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत पहला काम मिट्टीतेल लाइन को स्मार्ट रोड में तब्दील करना है। कंसलटेंट इस सड़क को बनाने की योजना तैयार करेगा और स्मार्ट सिटी वाली कंपनी सड़क का निर्माण करेगी। इसी के साथ एक बार फिर निगम यहां अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने की तैयारी में है ताकि शहर का कंसलटेंट को यहां सड़क निर्माण के लिए खाली जगह उपलब्ध कराई जा सके। सड़क को

इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसके तैयार होने से कलेक्टोरेट के सामने, शेफर स्कूल चौक, मुंगेली नाका चौक, स्वीमिंग पुल के सामने, मंगला चौक में लगने वाले जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी। मालूम हो कि स्मार्ट सिटी में इस सड़क को शामिल करने से एक बार फिर सड़क की चौड़ाई 80 फीट ही रखने तैयारी शुरू हो गई है। इससे रसूखदार बेजा कब्जाधारी फिर निगम के निशाने पर आ गए हैं।

'36 छत्तीसगढ़िया' प्रोजेक्ट बनाएगा बिलासपुर को स्मार्ट

बिलासपुर। शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए नगर निगम मूल योजना के साथ '36 छत्तीसगढ़िया' प्रोजेक्ट पर भी काम करेगा। इसके तहत शहर के अंदर 1-1 करोड़ रुपए की 36 योजनाएं आम लोगों की राय लेकर तैयार की जाएंगी। इस तरह शहर को आधुनिक रूप देने में जनता भी योगदान देगी।
तीसरे चरण के 30 स्मार्ट सिटी में बिलासपुर का नाम 19 वें स्थान पर है। घोषणा के साथ ही निगम की योजनाओं पर अलम करने की तैयारी शुरू हो गई है। विकास का मूल प्रोजेक्ट विशेषज्ञ कंसलटेंट तैयार करेंगे। इसके अलावा शहर को आधुनिक रूप देने में आम लोगों का भी योगदान सुनिश्चित किया गया है।

जनता की राय से 36 प्रोजेक्ट तैयार होंगे। शहर के किसी खास हिस्से में क्या काम होना है, यह आम लोगों के वोट से तय होगा। ऐसे हर प्रोजेक्ट के लिए 1-1 करोड़ रुपए आरक्षित किए गए हैं। स्मार्ट सिटी का काम शुरू होते ही निगम सबसे पहले कंसलटेंट से प्रोजेक्ट एरिया की प्लानिंग तैयार कराएगा। इसके बाद सिर्फ बिलासपुर के लिए 36 प्रोजेक्ट तैयार करने वोटिंग शुरू होगी।

सेंट्रल कमांड कंट्रोल करेगा ट्रैफिक
स्मार्ट सिटी एरिया के हर चौक-चौराहे और मुख्य मार्ग में स्मार्ट कैमरे लगाए जाएंगे। ये ऑनलाइन सेंट्रल कमांड जोन से जुड़े होंगे। इससे शहर के ट्रैफिक पर अधिकारी सीधे नजर रख पाएंगे। किसी चौक पर जाम लगने पर अधिकारी कंट्रोल रूम से ही ट्रैफिक डायवर्ट कर देंगे। इसी तरह ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वाले के घर दूसरे ही दिन चालान पहुंच जाएगा। उम्मीद है कि इस व्यवस्था से ट्रैफिक जाम की समस्या दूर हो जाएगी।

नहीं जाना पड़ेगा कार्यालय, मोबाइल एप से होगा काम

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत विशेष एप भी लॉच किया जाएगा। इससेसभी सरकारी विभाग जोड़े रहेंगे। शहर से संबंधित जानकारी एप से मिल जाएगी। लोग अपनी शिकायत भी कर पाएंगे और किसी काम के लिए आवेदन भी दिया जा सकेगा। इस एप की मानिटरिंग जिले के आला अधिकारी और विभाग प्रमुख रहेंगे। ऑनलाइन मिलने वाली शिकायतों के निराकरण पर जवाब मांगा जाएगा।

मिट्टीतेल लाइन में स्मार्ट रोड
प्रोजेक्ट में किसी नई सड़क को स्मार्ट रोड बनाने का प्रस्ताव मांगा गया है। इसके लिए रायपुर रोड से मिट्टीतेल लाइन होते हुए उसलापुर तक की सड़क का चयन करने पर विचार चल रहा है। सड़क पर स्मार्ट सिग्नल, लाइनर, स्मार्ट स्पीड ब्रेकर, स्ट्रीट लाइट आदि की सुविधाएं होंगी।

नलों में 24 घंटे पानी, जमीन के नीचे बिजली लाइन
स्मार्ट सिटी में 24 घंटे बिजली और पानी की सुविधा लोगों को मिलेगी। बिजली के सभी खंभों को हटाकर सड़कें चौड़ी की जाएंगी। बिजली अंडर ग्राउंड तारों से मिलेगी। इससे सड़कों की स्थिति बेहतर होने की बात कही जा रही है।

टूटेंगे निगम के स्कूल
शहर के पुराने मुन्नूलाल शुक्ला, लाल बहादुर शास्त्री, देवकीनंदन दीक्षित, नागोराव शेष, लाला लाजपतराय स्कूल को तोड़कर उसकी जगह पर मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएगी। जहां स्कूल को एक मंजिल पर लगाया जाएगा। इसके अलावा मल्टीलेवल पार्किंग, गार्डन आदि होंगे। इस तरह शहर में मौजूद जगह का पूरा उपयोग करने की तैयारी है।

निगम की कंपनी को मिलेगी जिम्मेदारी
स्मार्ट सिटी के लिए नगर निगम ने एक कंपनी पहले से तैयार कर ली है। इसका नाम बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड रखा गया है। इसके चेयरमैन नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव होंगे। जबकि कामकाज कंपनी के सीईओ नगर निगम आयुक्त कराएंगे। इनके अलावा कलेक्टर, एसपी, सीईओ चिप्स, केंद्र के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे।

दो कंसलटेंट बनाएंगे नक्शा
शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए दो विशेषज्ञ कंसलटेंट की मदद ली जाएगी। पहला कंसलटेंट अपनी टीम के साथ शहर के भौगोलिक क्षेत्रफल(इंफ्रास्ट्रक्चर) के हिसाब से योजना तैयार करेगा। दूसरा आईटी विशेषज्ञ होगा। वह पूरे शहर को वाईफाई जोन में बदलने, सीसीटीवी कैमरे लगाने आदि की योजना तैयार करेगा।

19 वार्ड होंगे शामिल
क्रमांक वार्ड पार्षद
10 राजेंद्रनगर संजय यादव
12 मदर टेरेसा नगर पंचराम सूर्यवंशी
13 आंबेडकर नगर मीनाक्षी बोमार्डे
14 क्रांतिकुमार भारतीय रामा बघेल
15 लक्ष्मीबाई नगर शेख नजीरूद्दीन
16 दीनदयाल उपाध्याय मीना गोस्वामी
21 निराला नगर तैय्यब हुसैन
22 आजाद नगर उषा मिश्रा
23 अशरफउल्ला नगर मुकीम कुरैशी
27 लाला लाजपतनगर शहजादी कुरैशी
28 शिवाजी नगर रजनी सोनी
29 रविदास नगर राजकुमार पमनानी
34 गांधी नगर शैलेंद्र जायसवाल
आंशिक प्रभावित वार्ड
24 रामनगर दीपांशु श्रीवास्तव
25 सुभाष नगर पुष्पा दुबे
26 मुन्नूलाल शुक्ला कमल कौशिक
30 नागोराव शेष अतुल बापते
31 कृष्णा नगर धनराज देवांगन
32 बसंत भाई पटेल रोशन राही

स्मार्ट सिटी एक नजर
शहर का कुल एरिया 6500 एकड़
प्रोजेक्ट एरिया 1041 एकड़
स्मार्ट वार्ड 19
कुल लागत 3900 करोड़
केंद्र की भागीदारी 500 करोड़
राज्य की भागीदारी 250 करोड़
निगम देगा 250 करोड़
अन्य योजनाओं की राशि 1100 करोड़
पीपीपी मॉडल से आएगा 1800 करोड़
स्मार्ट रोड मिट्टी तेल लाइन
स्मार्ट बाजार शनिचरी बाजार
स्मार्ट बस्ती मिनी बस्ती
ई रिक्शा 500
प्रोजेक्ट समय 5 साल
मल्टीलेवल पार्किंग 4
कंसलटेंट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट
आक्सीजोन व्यापार विहार

इसकी भी सुनें

बिलासपुर के लिए बड़ी उपलब्धि
शहर का स्मार्ट सिटी में चयनीत होना बड़ी उपलब्धि है। पिछले प्रस्ताव में जिस बातों पर आपत्ति हुई थी, उसे हटा दिया था। हमारे प्लान में शहर की छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखा गया है। अब कंसलटेंट नियुक्त कर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। - **सौमिल रंजन चौबे, आयुक्त, नगर निगम**

आधुनिक शहरों की तरह होगा विकास
स्मार्ट सिटी में बिलासपुर का चयन होने का लाभ शहरवासियों को मिलेगा। इसके लिए लोगों को बधाई। इस प्रोजेक्ट के आने से अब शहर का विकास भी आधुनिक शहरों की तरह करने में मदद मिलेगी। इसमें लोगों के हर जरूरत का ध्यान रखा गया है। - **किशोर राय, महापौर**

सरकार को देना चाहिए पूरा फंड
स्मार्ट सिटी के लिए केंद्र और राज्य सरकार सीमित राशि दे रही है। शेष फंड निगम को अपने संसाधनों और पीपीपी मॉडल से लाना है। ऐसा हुआ तो प्रति परिवार 30 हजार रुपए तक सालाना टैक्स निगम को लगाना होगा। केंद्र और राज्य शासन को पूरा फंड देना चाहिए। - **शैलेंद्र जायसवाल प्रवक्ता, कांग्रेस पार्षद दल**

कुछ मोहल्ले ही होंगे स्मार्ट
शहर को स्मार्ट नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि कुछ मोहल्लों में ही स्मार्ट सिटी का काम होगा। आधे से ज्यादा शहर प्रोजेक्ट से बाहर है। इसे स्मार्ट सिटी नहीं स्मार्ट मोहल्ला कहना उचित होगा। योजना के नाम पर शहरवासियों के साथ छलावा हो रहा है। - **शेख नजीरूद्दीन, नेता प्रतिपक्ष**
प्रोजेक्ट को लेकर चुनौतियां
सड़क- स्मार्ट सिटी के लिए सबसे पहले ट्रैफिक को सुधारना होगा। वर्तमान में शाम होते ही पूरे शहर में जाम लग जाता है। प्रोजेक्ट में कंसलटेंट ने एक भी फ्लाईओवर, अंडरब्रिज प्रस्तावित नहीं किया है। ऐसे में सड़क चौड़ी करना ही विकल्प बच जाता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और जमीन अधिग्रहण की जरूरत होगी।
सरकारी जमीन की कमी- स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट एरिया 1041एकड़ है। इसमें सिर्फ 51 एकड़ ही सरकारी जमीन है, वो भी टूकड़ों में। ऐसे में वहां विकास कार्य प्रस्तावित करना आसान नहीं होगा। जगह के अभाव में बड़े प्रोजेक्ट लाना चुनौती है।

फंड का अभाव- स्मार्ट सिटी योजना में केंद्र केवल 500 करोड़ और राज्य शासन 250 करोड़ रुपए देगा। निगम को अपनी आय से 250 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में लगाना है। जबकि यहां वेतन देने के लिए ही पैसे नहीं हैं। ऐसे में इतने बड़े फंड की व्यवस्था करना चुनौती होगी। प्रोजेक्ट एरिया में मौजूद सरकारी जमीनों को बेचकर इस राशि की व्यवस्था करने की तैयारी है। यह भी आसान नही होगा।
प्रोजेक्ट का समय- शहर में 400 करोड़ रुपए की सीवरेज परियोजना 9 साल में पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में 3966.2 करोड़ की स्मार्ट सिटी परियोजना को समय में पूरा करना बड़ी चुनौती होगी।
शेष शहर का विकास- शहर कुल 6500 एकड़ क्षेत्र में से केवल 1041 को स्मार्ट सिटी में रखा गया है। ऐसे में बचे हुए हिस्से को उसी के अनुरूप विकसीत करना बड़ी चुनौती साबित होगी।

योजना पर एक नजर

प्रोजेक्ट एरिया में जनसंख्या 84111 व्यक्ति

घर 16585

सड़क 27.6 किलोमीटर

स्लम 53.5 एकड़

पार्क 3 प्रतिशत

सरकारी जमीन 55 एकड़

सफाई के काम से निगमकर्मी होंगे अलग

18/6/2017

नगर निगम अब तीसरे चरण के सफाई ठेके की तैयारी में जुट गया है। इस बार नालियों की सफाई और मलबा हटाने का काम निजी हाथों में दिया जाएगा। इसके साथ ही सफाई एक ऐसा काम होगा जिसमें सौ प्रतिशत काम ठेके पर चला जाएगा।

नगरीय प्रशासन विभाग ने सफाई कर्मियों के पद को डाइंग कैडर घोषित कर दिया है। मतलब जो सफाई कर्मी फिलहाल काम कर रहे हैं उनके सेवानिवृत्त होते ही पद भी खत्म हो जाएगा। इसे देखते हुए सफाई के काम को अब निजी हाथों में सौंपने की तैयारी शुरू हो गई है। पहले चरण में घर-घर से कचरा उठाने के काम को ठेके पर दिया जा चुका है। एमएसडब्ल्यू साल्यूशन नाम की ठेकेदार कंपनी घरों से कचरा उठाने का काम 40 वार्डों में शुरू कर चुका है। इस कचरे को प्रोसेसिंग करके खाद और उद्योगों में जलने वाला ईंधन तैयार किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में सड़कों की सफाई का काम भी ठेके पर दिया जाएगा। सामान्य सभा ने उसका अनुमोदन भी कर दिया है। अब ठेका देने की तैयारी अंतिम चरण में है। इसके साथ निगम में सफाई के लिए तीसरे चरण के काम की तैयारी शुरू हो गई है। इसमें ठेकेदार को शहर की नालियों की सफाई करानी होगी। ठेकेदार नालियों को साफ करने के अलावा उससे निकले मलबे को भी डंपिंग पाइंट तक पहुंचाएगा। फिलहाल इस काम को नगर निगम के नियमित सफाई कर्मचारियों के जरिए कराने की योजना है। चूंकि नियमित सफाई कर्मियों में ज्यादातर महिलाएं ही बची हैं। ऐसे में उनसे नालियों की सफाई कराना उचित नहीं माना जा रहा है। ऐसे में पूरे नियमित कर्मचारियों को सफाई के काम से अलग करके उनका सारा काम ठेकेदारों के जरिए कराने की तैयारी है। निगम अधिकारियों का मानना है कि इससे शहर की सफाई कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से होगी।

ये हैं तीन चरण

पहला चरणः घर-घर से कचरा उठाना। काम चालू हो गया है

दुसरा चरणः सड़कों की सफाई कराना। सामान्य सभा से मिली अनुमति, अब ठेके की तैयारी।

तीसरा चरणः नालियों की सफाई। इसका ठेका कैसे कराया जाएगा इस पर योजना तैयार की जा रही है।

नियमित महिला सफाई कर्मियों से नाली सफाई नहीं कराई जाएगी। वैसे भी उनका पद डाइंग कैडर का है। ऐसे में नालियों की सफाई का काम भी ठेकेदारों से कराए जाएंगे।

सौमिल रंजन चौबे

आयुक्त, नगर निगम

निगम की नई बनी सड़क की खुदाई, बीएसएनएल पर 1 लाख जुर्माना

16/7/2017

नगर नगम ने विनोबा नगर की गायत्री मंदिर रोड पर दो दिन पहले ही डामरीकरण किया था जिसे बगैर अनुमति बीएसएनएल ने शनिवार को खुदाई कर दी। इससे पूरी सड़क खराब हो गई। इस पर निगम ने उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगया है। जल्द रकम जमा नहीं करने पर कार्यालय सील करने की चेतावनी भी दी गई है।

दो साल से बिनोबा नगरवासी जर्जर गायत्री मंदिर रोड से परेशान हैं। कई विवादों के बाद निगम ने इसका डामरीकरण शुरू कराया है। दो दिन पहले ही यहां की खराब सड़क पर डामरीकरण किया गया था। अब मोहल्ले वालों की शिकायत आई कि नई सड़क की किसी ने खुदाई कर दी। जांच में पता चला कि बीएसएनएल निगम से बगैर अनुमति लिए इस नई सड़क को केबल सुधारने के नाम पर खोद रहे हैं। इससे पूरी सड़क खराब हो गई है। इसे देखते हुए उपायुक्त मिथिलेश अवस्थी ने बीएसएनएल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना किया है। इसी के साथ यह भी चेतावनी दी गई है कि वे जुर्माने की राशि जल्द पटाएं अन्यथा उनका कार्यालय सील कर दिया जाएगा। इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। क्योंकि निगम ने अन्य टेलीफोन आपरेटरों को भी साफ कर दिया है कि अब अगर बगैर सूचना के शहर की किसी सड़क को खोदा तो उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई होगी।

रिलायंस ने भी किया परेशान

रिलायंस का केबल बिछाने का काम कर रहे ठेकेदार ने नेहरू चौक के पास पेयजल की पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसके चलते यहां लंबाई में पाइप लाइन को सुधारना पड़ा था। इसके अलावा पाइप बदलने के लिए गहरी खुदाई भी करनी पड़ी है। इन सब में पांच दिन का समय लग गया था। अब बीएसएनएल भी सड़क की खुदाई में जुट गया है।

विनोबा नगर की गायत्री मंदिर रोड नई बनी है। बीएसएनएल ने बगैर सूचना उसकी खुदाई कर दी। इसके चलते उन पर जुर्माना लगाया गया है। अगर जल्द राशि नहीं पटाएंगे तो इस बार उनका कार्यालय सील कर दिया जाएगा।

मिथिलेश अवस्थी

उपायुक्त, नगर निगम

स्मृति वन का 50 लाख का बिजली बिल ठेकेदार ने नहीं पटाया

14/6/2017

नगर निगम ने राजकिशोर नगर के स्मृति वन को पांच साल के लिए ठेके पर दिया था। ठेकेदार तीन साल में ही 50 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया छोड़कर भाग गया। ठेकेदार पर कार्रवाई करने के बजाय निगम ने फिर से गार्डन का पीपीपी मॉडल पर ठेका करा दिया है।

निगम शहर के उद्यानों का रखरखाव निजी हाथों में देने की तैयारी में है। इसी के तहत स्मृति वन को 16 जुलाई 2014 को द आर्ट फैक्ट्री प्रॉप नाम के फर्म के संचालक संदीप राजपूत को दिया गया था। तय शर्त के अनुसार सालाना 5 लाख 75 हजार रुपए शुल्क ठेकेदार को नगर निगम को देना था। शुरुआत में तो सबकुछ ठीक चला। इसके बाद ठेकेदार ने अपना रंग दिखाना शुरू किया

और सबसे पहले गार्डन का बिजली बिल का भुगतान रोक दिया। जो बढ़कर अब 50 लाख रुपए तक पहुंच गया है। इसके अलावा उसने गार्डन का रखरखाव भी बंद कर दिया जबकि आने जाने वालों से वह बकायदा टिकट की राशि वसूल रहा था। इसे देखते हुए अब फिर ठेकेदार का ठेका निरस्त करके नया टेंडर किया जा रहा है। अब की बार गार्डन को तीन हिस्सों में बांट दिया गया है। पहले हिस्से में लोगों के घूमने फिरने के लिए फ्री रहेगा। दूसरे हिस्से में बच्चों के गेम्स आदि होंगे। जबकि तीसरे हिस्से को पार्टी और विवाह समारोह आदि के लिए ठेकेदार किराए से दे सकेगा। निगम ने पहले स्मृति वन में विवाह आदि कराने की पाबंदी लगा रखी थी। माना जा रहा है कि इस बार मिली छूट के कारण ठेकेदार को उसके खर्च की भरपाई हो जाएगी। इधर पुराने ठेकेदार की निगम में जमा राशि राजसात करके बिजली बिल के नुकसान की भरपाई करने की तैयारी है।

स्मृति वन के पुराने ठेकेदार ने उद्यान का रख रखाव ठीक नहीं किया। इसके चलते नया ठेका किया जा रहा है। उसके बकाया बिजली बिल कीराशि ठेकेदार से वसूली जाएगी।

सौमिल रंजन चौबे

आयुक्त, नगर निगम

नगर निगम का विशेष सम्मेलन 16 को

13/6/2017

नगर निगम का विशेष सम्मेलन 16 जून को रखा गया है। इसमें शहर के अंदर बनने वाली विभिन्न कांक्रीट सड़क और विकास कार्यों के प्रस्ताव रखे गए जाएंगे। इस बार अध्यक्ष ने पहले ही साफ कर दिया है कि पार्षदों को केवल एजेंडा में ही चर्चा करने दिया जाएगा। वार्डों की समस्याओं पर कोई बात नहीं होगी। शहर में फिर पूरी सड़कों को नया बनाया जाना है। इसके लिए नगर निगम ने किस्तों में 40 करोड़ रुपए के टेंडर लगाए हैं। इस पर सामान्य सभा से मंजूरी लेना जरूरी है, ताकि उसे राज्य शासन को भेजा जा सके। इसके लिए निगम अध्यक्ष अशोक विधानी ने विशेष सम्मेलन का आयोजन किया है। इसमें विकास कार्य के प्रस्तावों पर चर्चा होगी।

सीवरेज ठेकेदार ने दो जगह डाली टूटी पाइप लाइन

10/6/2017

सीवरेज ठेकेदार ने आरपापार दो स्थानों पर जमीन के नीचे टूटी पाइप लाइन बिछा दी। इसकी वजह से गंदा पानी ट्रीटमेंट प्लांट के बजाय जमीन के नीचे जा रहा था। जांच में गड़बड़ी सामने आने पर निगम ने ठेकेदार को क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों को बदलने का निर्देश दिया है।

सीवरेज के ठेकेदार ने शहर में बिना जांच आनन-फानन में पाइप लाइन बिछाई है। पाइप डालने में किसी तरह की सतर्कता नहीं बरती गई। इसी का नतीजा है कि कई जगहों पर गंभीर समस्या सामने आ रही है। अरपा पार हुई जांच में पता चला है कि दो जगहों पर ठेकेदार ने टूटी पाइप लाइन बिछा दी है। इसमें से सीवर का गंदा पानी जमीन के नीचे रिसकर जा रहा था। हाईड्रोलिक टेस्ट में इसका खुलासा हुआ। राजकिशोर नगर के कल्याण बाग और चंदन आवास में यह गड़बड़ी सामने आने पर निगम ने ठेकेदार को टूटी पाइप लाइन उखाड़ कर नई लगाने का निर्देश दिया है। मामले में खास बात यह है कि दोनों ही जगह गलती हाईड्रोलिक टेस्ट में पकड़ी गई। इसे देखते हुए निगम ने अब ठेकेदार के काम को हाईड्रोलिक टेस्ट होने के बाद ही हरी झंडी देने का निर्णय लिया है। यहां यह बताना लाजमी है कि पूरे शहर में केवल राजकिशोर नगर ही एकमात्र कालोनी है, जहां सीवरेज सिस्टम काम कर रहा है। इस कालोनी के आधे हिस्से में लोगों ने सिवरेज सिस्टम से कनेक्शन जोड़ लिया है। यहां जिन लोगों ने अपना कनेक्शन जुड़वा, उनके घरों का पानी सीवरेज पाइप में जाने के बजाय ओवरफ्लो होने लगा था। इसके चलते उन्होंने सीवरेज से तौबा कर लिया।

चांटीडीह पंपिग स्टेशन में नहीं आ रहा पानी

नगर निगम अरपा पार सीवरेज सिस्टम चालू होने का दावा कर रहा है। जबकि वास्तविकता इसके उलट है। यहां के दो सीवरेज पंपिग स्टेशन में से एक चांटीडीह में सीवरेज का पानी नहीं आ रहा है। पंपिग स्टेशन सूखा होने के कारण इसे चालू नहीं किया गया है। केवल राजकिशोर नगर के पंपिग स्टेशन में ही आधी कालोनी से नाममात्र पानी आता है। ऐसी स्थिति में सुबह मुश्किल से एक घंटे तक पंपिग स्टेशन चालू करने के बाद पानी ट्रीटमेंट प्लांट पहुंच जाता है।

हाईड्रोलिक टेस्ट से बच रहा ठेकेदार

मुख्य शहर में सीवरेज ठेकेदार ने निगम अधिकारियों के अनुसार पाइप लाइन तो बिछा दी, लेकिन उसकी जांच कराने से कतरा रहा है। हाल यह है कि मुख्य शहर में कहीं भी पाइप लाइन का हाईड्रोलिक टेस्ट नहीं हुआ है। इससे पानी में लीकेज से लेकर सभी तरह की कमियां सामने आ जाती हैं।

सीवरेज सिस्टम के हाईड्रोलिक टेस्ट में दो जगहों पर पाइप लाइन में लीकेज मिला था। इसे फिर से उखाड़कर नई पाइप लाइन बिछवाई गई है।

सुरेश बरूआ

सहायक अभियंता, सीवरेज सेल

207 करोड़ देने पर खूंटाघाट से शहर को मिलेगा पानी

7/6/2017

शहर को खूंटाघाट से पानी देने के लिए सिंचाई विभाग ने नगर निगम से 207 करोड़ रुपए मांगे हैं। साथ ही अहिरन नदी को डैम से जोड़ने नई शर्त रख दी है।

शहर में पेयजल की सप्लाई भू-जल से होने पर जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है। ऐसे में अब खूंटाघाट बांध से पानी लाकर उसे फिल्टर करने की योजना बनाई गई है। सिंचाई विभाग से सहमति मिलने के बाद निगम ने केंद्र की अमृत मिशन योजना के तहत पाइप लाइन और फिल्टर प्लांट बनाने के प्रोजेक्ट को भी स्वीकृत करा लिया है। वहीं 201 करोड़ रुपए का टेंडर जारी करमुंबई की ठेकेदार कंपनी इंडियन ह्यूम पाइप को वर्कआर्डर भी जारी कर दिया है। अब जब काम शुरू कराने की बारी आई तो सिंचाई विभाग ने इसमें नई शर्त जोड़ दी है। इसमें कहा गया है कि निगम को विभाग तब तक पानी नहीं देगा जब तक खूंटाघाट से अहिरन नदी जुड़ नहीं जाती। नदी जोड़ने के लिए विभाग के 467.50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। निगम को इस लागत में से 207 करोड़ रुपए बतौर एडवांस विभाग को देने होंगे। इसे बाद में पानी बिल से काटा जाएगा। इस तरह इन दो नई शर्तों के कारण निगम के अफसर असमंजस में पड़ गए हैं। कारण यह है कि विभाग की ओर से मांगी गई इस अतिरिक्त राशि को निगम ने अपने प्रस्ताव में शामिल नहीं किया था। केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद उसमें फिर से बदलाव कराने को भी बहुत कठिन माना जा रहा है। इसी तरह अहिरन नदी से खूंटाघाट को जोड़ने का प्रस्ताव भी फिलहाल प्रारंभिक दौर में है। इसमें केंद्र की सहमति और नदी जुड़ने में ही कम से कम 10 साल का समय लगने की बात कही जा रही है।

सिंचाई विभाग की शर्त

0 पानी अहिरन नदी और खूंटाघाट जुड़ने के बाद दिया जाएगा।

0 निगम को नदी जोड़ने में आने वाली लागत के 207 करोड़ रुपए पहले देने होंगे।

0 खूंटाघाट बांध से पानी ले जाने की व्यवस्था निगम को खुद करनी होगी।

0 शासन की ओर से निर्धारित जलकर देना होगा।

पाइप लाइन बिछाने की है तैयारी

नई शर्त से एक ओर जहां मामला उलझ गया है वहीं ठेकेदार बारिश के बाद खूंटाघाट से बहतराई तक नहर के किनारे पाइप लाइन बिछाने का काम शुरू करने की तैयारी में है। इसके बाद बहतराई में बांध के पानी को फिल्टर करने के लिए प्लांट भी प्रस्तावित है।

अब क्या होगा

नगर निगम अब नई शर्त को लेकर राज्य जल उपयोगिता समिति में जाने की तैयारी कर रहा है। इसके पीछे कारण यह है कि वहां मिले अनुमोदन के बाद ही अमृत मिशन के तहत पेयजल की योजना स्वीकृत कराई गई थी।

किसानों के लिए भी नहीं है पानी

सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के अनुसार खूंटाघाट में किसानों को देने लायक पानी भी नहीं आता। बांध में पानी का भराव 230.78 मिलियन क्यूबिक मीटर रहता है। इससे 48 हजार 785 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को खरीफ में पानी देने का लक्ष्य है। इस तरह विभाग को केवल एक सीजन के लिए ही 244 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी चाहिए, जो लभराव की तुलना में 13.22 मिलियन क्यूबिक मीटर कम है। इस तरह सिंचाई विभाग के पास फिलहाल किसानों के लायक भी बांध में पानी नहीं है।

नगर निगम को हमने साफ कर दिया है कि खूंटाघाट से पानी तभी दिया जा सकता है, जब अहिरन नदी को उससे जोड़ दिया जाएगा। साथ ही निगम को नदी जोड़ने के प्रोजेक्ट के लिए भी 207 करोड़ रुपए देने होंगे।

आरपी साव

कार्यपालन अभियंता, खारंग डिवीजन, जल संसाधन विभाग

पेयजल के लिए पानी देना किसी भी बांध के लिए पहली प्राथमिकता होती है। सरकार ने भी सभी बांध में 20 प्रतिशत पानी पेयजल के लिए आरक्षित कर दिया है। हमें अपने हिस्से का पानी चाहिए। इसके लिए टेंडर कर दिया गया है। ठेकेदार जल्द ही काम भी शुरू करने वाला है।

अधिकारी भी अचरज में, कैसे टिकी है सड़क

3/6/2017

गांधी चौक से तारबाहर तक सीवरेज ठेकेदार द्वारा बनाई गई सड़क की पीडब्ल्यूडी, सीवरेज सेल और ठेकेदार के इंजीनियरों ने 19 जगहों में खोदकर जांच की। इस दौरान तीन जगहों पर बिना बेस किए ही डामरीकरण करने की चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। जबकि अन्य जगहों पर तय मापदंड से कम मटेरियल का उपयोग किया गया है। इस स्थिति को देखते हुए कांग्रेस पार्षद दल ने इसे आर्थिक अनियमितता का मामला मानते हुए जांच रिपोर्ट के आधार पर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में शिकायत करने की धमकी दी है।

बिहारी टॉकीज के सामने सड़क धंसने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद उसी जगह के आसपास फिर सड़क धंसने लग गई। लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद गांधी चौक से लेकर तारबाहर तक 1.10 किलोमीटर सड़क की जांच पीडब्ल्यूडी, सीवरेज सेल, स्थानीय पार्षद की टीम से कराने का निर्णय हुआ था। इसी के तहत सुबह 8 बजे से 50-50 मीटर की दूरी पर सड़क में चार बाई तीन फीट का गड्ढा खोदकर मटेरियल (डामर, गिट्टी और मुरुम) की जांच की गई। शुरुआत मोहनलाल ताराचंद की दुकान के सामने से हुई। जांच शुरू हुई तो खोदते ही बेस के जरूरी मटेरियल की मात्रा तय मापदंड से बहुत कम मिली। तीन जगह तो ऐसी थी जहां सीवरेज के ठेकेदार सिम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों ने बिना बेस सड़क बना दिया था। तीनों जगहों में मुरुम की मात्रा शून्य मिली। इसे लेकर जांच कर रहे इंजीनियर भी अचरज में थे कि आखिर बिना बेस डाले बनाई गई सड़क इतने दिन चल कैसे गई। 19 जगह सैंपल जांची गई और सभी जगह का गुणवत्ताहीन काम होने की पुष्टि हुई है। इसके बाद पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने साफ कर दिया है कि जब तक नए सिरे से बेस तैयार नहीं किया जाता तब तक वे इस सड़क पर हाथ नहीं डालेंगे।

इन्होंने की जांच

0 एम सरकार, कार्यपालन अभियंता सीवरेज सेल

0 मघेश्वर प्रसाद, कार्यपालन अभियंता पीडब्ल्यूडी

0 इंजी. शैलेंद्र जायसवाल पार्षद

0 जीआर जांगड़े एसडीओ पीडब्ल्यूडी

0 सुरेश बरुआ एसडीओ निगम

0 बिंद्रा प्रसाद उप अभियंता पीडब्ल्यूडी

0 हिमांशु मिश्रा सीवरेज सेल नगर निगम

0 इंजी.अविनाश सिंह मेकेडम मेकर्स रायपुर प्राइवेट लिमिटेड

पानी पड़ा तो पूरी सड़क धंसेगी

निगम इंजीनियरों और सीवरेज ठेकेदार सिम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर तारबाहर से गांधी चौक तब गड्ढा किया और उसमें मिट्टी भरकर सड़क बना दी। बेस भी बेहद घटिया गुणवत्ता से निकल गया। ऐसे में इंजीनियरों का मानना है कि इस सड़क में जब भी पानी पड़ा तो पूरी धंस जाएगी। फिलहाल जांच के केवल बेस की हुई है।

पूरी सड़क में होल

सड़क के ऊपर हिस्से को जेसीबी से उखाड़कर जब उसमें लोहे का राड डालकर देखा गया तो अंदर जमीन पूरा होल निकला। लोहे का राड बहुत आसानी से अंदर जा रहा है। ऐसे में केवल बेस ठीक करके सड़क बना भी दी गई तो भी इसके टिकाऊ नहीं होने की बात कही जा रही है।

सीवरेज ठेकेदार पर 30 लाख का जुर्माना

सीवरेज ठेकेदार ने जोन 1 ए में पाइप लाइन डालने का काम पूरा कर लिया है। इसके बाद ठेकेदार को डली हुई पाइप लाइन का हाइड्रोलिक टेस्ट करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी दो माह से ठेकेदार ने जांच नहीं की। काम में लापरवाही बरतने के कारण ठेकेदार पर 30 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। इसके बाद भी उसने जांच नहीं की तो आगे और बड़ी राशि का जुर्माना करने की चेतावनी दी गई है। यहां यह बताना लाजिमी है कि पाइप लाइन की जांच किए बिना ही बारिश को देखते हुए निगम को ऊपर सड़क का काम कराना पड़ रहा है। अगर जांच में पाइप लाइन ठीक जगह पर लगना नहीं मिली फिर नई सड़क को खोदकर गलती को सुधारना पड़ सकता है।

गांधी चौक से लेकर तारबाहर तक सड़क की जांच की गई है। इसमें कहीं भी बेस का काम ठीक नहीं मिला है। रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसके बाद यह तय किया जाएगा कि वहां क्या करना है।

मघेश्वर प्रसाद

कार्यपालन अभियंता, पीडब्ल्यूडी

पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट का इंतजार है। जांच में तो गड़बड़ी मिली है। इसके बाद अधिकारी जैसा चाहेंगे वैसे काम कराया जाएगा।

एम सरकार

सीवरेज सेल प्रभारी, नगर निगम